

‘मौका मौका हर बार धोखा’

कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ बुकलैट जारी की

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 दिसम्बर। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार और केन्द्र सरकार की कारगुजारियों पर एक पुस्तिका जारी की है।

पुस्तिका का शीर्षक है “मौका मौका हर बार धोखा”। पुस्तिका को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने जारी की है, इस दौरान वरिष्ठ पार्टी नेता अजय माकन और काजी निजामुद्दीन भी मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है। जनता दोनों के बीच पिस रही है। इन दोनों ने दिल्ली को नफरत का बाजार बना दिया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “कोविड महामारी के दौरान, लोगों को अपने रिश्तेदारों के शवों के लिए कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन और

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि आप 11 साल से दिल्ली में सत्तारूढ़ है और भाजपा 2014 से केन्द्र में, पर दोनों के आरोप-प्रत्यारोप में दिल्ली की जनता फंस गई है। दोनों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है।
- बुकलैट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने जारी की। इस दौरान पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन तथा वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन मौजूद थे।

आई.सी.यू. को कमी पड़ गई थी। उस समय, दिल्ली सरकार अस्पताल बनवाने के बजाय, “शीश महल” बनाने पर पैसा खर्च कर रही थी और उधर भाजपा के केन्द्र सरकार “सैन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट” का निर्माण कर रही थी।

पूर्व मुख्यमंत्री तथा आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुये, माकन ने कहा, “वे अपनी जेब में 2 रु. वाला पैसा रखते हैं, अपनी पार्टी का नाम “आम आदमी पार्टी” रखा है, लेकिन स्वयं किसी राजा की तरह “शीश महल” में रहते हैं।

इसी प्रकार के भाव व्यक्त करते हुये, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा, “आप दिल्ली में पिछले 11 साल से सत्ता में है और भाजपा 2014 से केन्द्र में सत्ता में है। दिल्ली की जनता ने इन दोनों सरकारों को बड़ी आशाओं-अपेक्षाओं के साथ चुना था, लेकिन इतने वर्षों में जनता के हिस्से में केवल झूठे वादे तथा विश्वासघात ही आये हैं।”

दिल्ली के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुये, यादव ने जोर देते हुये कहा कि 15 वर्षों के कांग्रेस शासन के दौरान, चाहे

विकास का मोर्चा रहा हो या सामाजिक क्षेत्र का, पार्टी ने शासन-प्रशासन के नये आयाम हासिल किये। उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार ने, गरीबों, महिलाओं तथा युवाओं सहित, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया था। उन वर्षों में दिल्ली को विश्व-स्तरीय शहर बनाने के लिये एक मजबूत नींव रखी गई थी।”

कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी निजामुद्दीन ने कहा, “आप और भाजपा एक-दूसरे पर दोषारोपण का खेल खेलती रहेंगी। जनता के लिये काम केवल कांग्रेस ही करेगी। दिल्ली में अपने बलबूते पर सत्ता में लौटने के विश्वास के साथ, पार्टी आगामी विधानसभा अकेले ही लड़ेगी। अब तक पार्टी दो सूचियों जारी कर चुकी है। पार्टी ने मंगलवार रात को आगामी चुनावों के लिये 26 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में शामिल प्रतिष्ठित उम्मीदवारों में राजेश लिलोटिया (सीमापुरी) तथा मुकेश शर्मा (उत्तम नगर) शामिल हैं। दिल्ली की 70 सीटों के विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरु में होने हैं।

क्या होगा दिल्ली की महिला सम्मान व संजीवनी योजनाओं का

दिल्ली सरकार के दो विभागों ने इन योजनाओं को अवैध बताते हुए नोटिस छपवाये

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर विवाद खड़ा हो गया है। संबंधित विभाग ने नोटिस जारी कर जनता को अगाह किया है कि ये योजनाएं अभी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं की गई है। एक सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।

विभाग ने कहा, इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या जानकारी एकत्र कर रहा है वह जनता से धोखाधड़ी कर रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि “विभिन्न समाचार चैनलों/प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आया है कि दिल्ली के निवासियों के बीच “संजीवनी योजना” नामक एक कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिल्ली के सभी अस्पतालों (सरकारी या निजी) में आयु मानदंड की परवाह किए बिना फ्री उपचार प्रदान करने का दावा किया गया है।

“इसके अलावा यह भी विभाग के संज्ञान में आया कि इस योजना के तहत भौतिक फॉर्म भरकर नामांकन करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों/स्वयंसेवकों द्वारा पंजीकरण अभियान भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही कथित पंजीकरण फॉर्म में वरिष्ठ नागरिकों का विवरण मांगा जा रहा है, जिसमें फोन नंबर, पता, आधार और बैंक खाते का विवरण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों के अनुसार, हाल ही में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के बीच एक बैठक हुई थी और उनसे सीएम के खिलाफ कोई झूठा मामला बनाकर सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है।

केजरीवाल ने कहा कि हमने महिला सम्मान योजना और वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सूचना निकलवाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होगी- आतिशी

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर यह नोटिस जारी किया है कि ये योजनाएं अस्तित्व में नहीं हैं। आतिशी ने कहा, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, योजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों के अनुसार, हाल ही में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के बीच एक बैठक हुई थी और उनसे सीएम के खिलाफ कोई झूठा मामला बनाकर सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है।

केजरीवाल ने कहा कि हमने महिला सम्मान योजना और वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाइवे के किनारे मवेशियों के लिए शैल्टर बनेंगे, जोधपुर से होगी शुरुआत

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मवेशियों के कारण होने वाले सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए यह योजना बनाई है

—जाल खंभात—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 दिसम्बर। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने व मवेशियों के कारण होने वाले सड़क हादसों को चुनौतियों से निपटने के लिए सड़क किनारे मवेशियों के लिए शैल्टर खोलने पर विचार कर रही है।

एन.एच.ए.आई. की इस पहल का उद्देश्य सड़क-यात्रियों के लिये अधिक सुरक्षित यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना तथा कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आ जाने वाले आवारा पशुओं की समस्या से निबटारा है।

हालांकि, इस दिशा में पहले भी कई कदम उठाये गये हैं, लेकिन उन्हें कई सामाजिक तथा संवेदनशील मुद्दों के चलते अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये शैल्टर क्षेत्र 0.21 से 2.29 हेक्टेयर में बनेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत, ये शरणगाह आवारा पशुओं

- यह योजना जोधपुर रिंग रोड के डांगियावास से जयवाल सैक्शन के बीच एन.एच. 112 पर शुरु होगी।
- यू.पी. व हरियाणा बॉर्डर से एन.एच. 334 बी पर भी शैल्टर बनाए जाएंगे।
- सूत्रों ने बताया कि शैल्टर में मवेशियों के लिए चारा व पानी के साथ इलाज की भी व्यवस्था होगी।

के लिये सुरक्षित स्थानों पर रणनीतिक रूप से स्थापित किये जायेंगे तथा इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके आने-जाने में कमी आ जायेगी।

इस योजना की क्रियान्विति राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 112 पर जोधपुर रिंग रोड के जोधपुर सैक्शन के डांगियावास-जयवाल क्षेत्र के साथ ही, अन्य कई राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों पर की जायेगी। इनमें एन.एच.-334 बी का उत्तर प्रदेश-हरियाणा बॉर्डर सैक्शन भी शामिल है, जहाँ ये शरणगाह खरखोड़ बाईपास पर तथा एक अन्य शरणगाह एन.एच.-148 बी के

विभागीय-हॉर्सी सैक्शन के हॉर्सी बाईपास पर बनाया जायेगा। विभिन्न राज्यों की बहुत सी अदालतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की आवाजाही के कारण होने वाले बदलावों के प्रस्तावों के लिये बहुत उत्सुक थीं। एन.एच.ए.आई. ने वर्तमान कन्सेशनरियर, गावर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एपीएमएट पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इन अनुबंध के तहत, कन्सेशनरियर एन.एच.ए.आई. द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर केटल-शैल्टरों का निर्माण करेगा। यह कंपनी इन शैल्टरों का रख-रखाव भी करेगी,

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। हाल ही में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार व मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई। अब इन सभी चर्चाओं के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा और भाजपा मुख्यालय में उनका कार्यक्रम विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है।

केन्द्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत, शुक्रवार को प्रदेश के 1.50 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। प्रदेश के पुराने 33 जिला मुख्यालयों पर पट्टे बांटे जाएंगे।

इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वरुंचुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

राजस्थान, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ को बाघ मिलेंगे

भोपाल, 25 दिसम्बर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर, राज्य शासन द्वारा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य को बाघ हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जारी आदेश में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से राजस्थान को 4 मादा बाघ, उड़ीसा को एक नर एवं 2 मादा बाघ और छत्तीसगढ़ राज्य को 2 नर एवं 6 मादा

मध्य प्रदेश राजस्थान को 4 मादा बाघ देगा।

बाघ सौंपे जायेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि बाघ देने की सैद्धांतिक प्रक्रिया में बाघ एवं बाघिन को ट्रांसलोकेट करने की कार्यवाही अधिकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में की जाये। बाघों के जीवन को किसी प्रकार का खतरा न हो, इसका ध्यान रखा जाये। ट्रांसलोकेट किये जाने का सम्पूर्ण व्यय संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। हस्तांतरण की विधिवत अनुमति केन्द्र सरकार से प्राप्त की जाये।

2025 में भारत की पर्यटन ग्रोथ रेट चीन को भी पीछे छोड़ देगी

भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 17 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर। सन् 2025 में भारत से अन्य देशों को जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी जाएगी तथा 29 मिलियन पर्यटकों की यह अनुमानित संख्या, जहाँ, चीन का मात्र 20 प्रतिशत है, वहीं, भारत की पर्यटन ग्रोथ रेट के उत्तरी पड़ोसी देश को पीछे छोड़ रही है। बीसा में छूट के कारण भारतीय यात्रियों में से अधिकतर एशिया के अंदर यात्रा करेंगे, लेकिन प्रमुख गंतव्य स्थानों में मिडिल ईस्ट और अमेरिका भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि भारतीय पर्यटक औसतन 1400 डॉलर प्रति व्यक्ति खर्च करेंगे, जो कि 1,033 डॉलर वैश्विक औसत से काफी अधिक है।

वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म काउन्सिल का अनुमान है कि भारत का पर्यटन उद्योग वर्ष 2034 तक दोगुना हो कर 523 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा, इससे विभिन्न रिस्क के 1.8 करोड़ रोजगार सृजित होंगे।

काउन्सिल की अध्यक्षा जूलिया सिम्पसन ने कहा, भारत पर्यटन क्षेत्र का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी योगदान है, लेकिन पर्यटन के विस्तार की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है, जो भारतीय पर्यटन उद्योग की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

ट्रेवल एण्ड टूरिज्म से जुड़ी कई अन्य संस्थाओं और फर्मों ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत के लिए उत्साहवर्धक भविष्यवाणियों की हैं और कहा है कि पर्यटन का स्तर जल्दी ही कोविड से पहले वाले स्तर तक पहुँच जाएगा।

वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म काउन्सिल (डब्ल्यू.टी.टी.सी.) के पूर्वानुमान के अनुसार, भारत का टूरिज्म सैक्टर 2034 तक प्रति व्यक्ति खर्च करेंगे, जो कि 1,033 डॉलर वैश्विक औसत से काफी अधिक है।

रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिससे इस क्षेत्र का कुल रोजगार 63 मिलियन तक पहुँच जाएगा। डब्ल्यू.टी.टी.सी. अध्यक्ष जूलिया सिम्पसन ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा हॉस्पिटैलिटी प्रमुख

आकर्षण हैं। देश की जी.डी.पी. में पर्यटन का योगदान 7 प्रतिशत है और यह विभिन्न प्रकार की रिस्क को रोजगार भी प्रदान करता है। सिम्पसन ने पर्यटन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी बात की। भारत में उत्सर्जित

कुल ग्रीन हाउस गैसों, खासकर कार्बन डाईऑक्साइड का 5 प्रतिशत पर्यटन की ही देन है। हालांकि पर्यटन का विस्तार जारी है, पर कार्बन पर्यटन की गति धीमी हो गई है, यह बात पर्यटन में बढ़ती दक्षता को दर्शाती है। सिम्पसन ने भारत सरकार के साथ मजबूत सहयोग पर जोर दिया ताकि जो परम्परा चली आ रही है, उन्हें प्रोत्साहन दिया, जा सके, खासकर उड्डयन क्षेत्र में। सिम्पसन ने एविग्रेशन फ्यूल के तहत उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने तटवर्ती क्षेत्रों एवं नैचुरल लैंड स्केप के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अक्षय ऊर्जा के प्रति संकल्प की तारीफ की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करंट से मौत, जयपुर डिस्कॉम पर 17.66 लाख का हर्जाना

जयपुर, 25 दिसम्बर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने 11 केवी के तार से करंट लगने के चलते युवक की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम पर 17.66 लाख रूपए का हर्जाना लगाया है। पीठासीन अधिकारी मुकेश परनामी ने डिस्कॉम को आदेश दिए हैं कि वह हर्जाना राशि

■ अतिरिक्त जिला न्यायालय ने करंट से मरने वाले युवक के परिजनों के परिवार पर यह आदेश दिया।

पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करे। अदालत ने चेताया है कि यदि 45 दिन में हर्जाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो डिस्कॉम को इस राशि पर नौ फीसदी ब्याज देना होगा। अदालत ने यह आदेश ढोढसर निवासी रेखा देवी व अन्य के परिवार पर दिए।

परिवाद में अधिवक्ता मुकेश व्यास ने अदालत को बताया कि 9 सितंबर, 2019 को रामकिशोर पर की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)